जो कहा-वो किया.... मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नया सड़क छाप जुमला

क्या कहा-क्या किया.... तीस साल से मंझावली पुल की बाट देख रहे फरीदाबाद निवासी

विवेक की विशेष रपट

रोज 45 किमी सड़क बनाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार के केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक नया सड़कछाप जुमला 'जो कहा वो किया' फरीदाबाद निवासियों के सामने परोस दिया है। इसमें निहित है, फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले मंझावाली पुल के 30 वर्ष से घोषित प्रोजेक्ट को इसी दिसम्बर तक पूरा करने का वादा।

फ़रीदाबाद वाले चाहें तो पलट कर पूछ सकते हैं-मंत्री जी, क्या कहा क्या किया? खैर, गुर्जर के दावे की असलियत जांचने के लिए निर्माणाधीन मंझावाली पुल की तरफ जाना तय हुआ। फरीदाबाद बाईपास से नहर पार करते ही खेड़ी पुल से होते हुए एक बेहद पतली सड़क मंझावाली पुल की तरफ बढ़ती है। यह सड़क इतनी पतली है कि दो ट्रक आमने-सामने निकल पायें, मुश्किल है।

सड़क पर आगे बढ़ने पर दोनों ओर घना रिहाइशी इलाका है। इस इलाके से होकर सारा ट्रैफिक फरीदाबाद क्षेत्र को कैसे पार कर सकेगा, ये खुफिया जानकारी मंत्री कृष्णपाल के पास ही मिल सकती है। ज्यों ज्यों आगे बढ़िये सड़क और पतली और संकरे मोड़ों से होते हुए मंझावाली पुल की तरफ बढ़ती है। अंत के तीन मोड़ कुछ ऐसे हैं कि एक भी ट्रक यदि मुड़ रहा हो तो पैदल निकल पाने लायक जगह भी नहीं बचेगी।

17 जून ही वो तारीख थी जब यहाँ से गाड़ी बिना किसी अवरोध के जा सकती थी। इसके पीछे कारण था अंतिम दो किमी की सड़क पर पुलिस का तैनात होना क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर ने पुल के नाम पर खालिस अपने चुनावी मतलब के विशाल भंडारे का आयोजन किया था। जी हां ट्रैफिक पुलिस के वही जवान गाँव वालों से खटिया-कुर्सी मांग पर अपनी दिहाड़ी लगा रहे थे जो अन्यथा सड़कों पर वसूलियां करते नजर आते हैं।

20 किमी के रास्ते में भाजपा के 4/6 के सैकड़ों फ्लेक्स बोर्डों की धूम थी। शायद ही कोई कोना या खम्भा होगा जिसपर कृष्णपाल गुर्जर और स्थानीय भाजपा नेताओं की शक्लों से सुशोभित विशाल भंडारे के आमंत्रण बोर्ड ना लगे हों। इन फ्लेक्सों पर होने वाला खर्च लाखों रुपये से कम नहीं हो सकता, जो इन नेताओं ने बेशक अपने किस खून पसीने से कमाए होंगे, बताने की जरूरत नहीं। सभी पोस्टर तो भाजपा नेताओं की शक्लें सुशोभित करते हुए भंडारा भंडारा चिल्ला रही थीं और पुल का निर्माण भारत सरकार करवा रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी किस बात का श्रेय ले रही है और कैसे? यदि ये पार्टी का समारोह है तो भारत सरकार की निर्माणाधीन साइट पर क्यों? पुलिस का प्रयोग पार्टी प्रोग्राम में कैसे? और यदि ये सरकारी प्रोजेक्ट है जो की है भी तो भाजपा कार्यकर्ता साइट पर भंडारा किस एवज में चला रहे हैं? क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा ही भारत है?

लूट की दुकान धड़ल्ले से चलाने वाली भाजपा सरकार का रास्ता कांग्रेस ने ही खोला है। इसी मंझावाली पुल का उद्घाटन 30 वर्ष पहले कांग्रेस के राजेश पायलट ने किया था7 तबसे लेकर आज तक कुछ हुआ हो या न हुआ हो, पर लिंग्यास इंस्टिट्यूट, नॉलेज पार्क इत्यादि पूंजीपति संस्थानों ने कौड़ियों के भाव जमीने खरीद कर पुल की तरफ जाने वाली इस संकरी सड़क पर भव्य इमारतें बना रखी हैं जो अब फायदे का निवेश बनेंगी।

मंझावाली साइट पर पहुँच कर पाया, सूखी यमुना में एक रोलिंग मशीन के

अलावा सिर्फ एक मजदूर कार्यरत था7 बाकी के सभी कामगार वहीँ भंडारा आयोजन में व्यस्त। सरकारी ठेकेदार पार्टी का भंडारा आयोजित करने में व्यस्त हो तो समझना मुश्किल नहीं कि कितना चढ़ावा चढ़ा होगा नेता रूपी देवताओं को। इसी सूखी नदी में कृष्णपाल गुर्जर जहाज चलाने का दावा भी कर रहे हैं। कैसे? भगवान जाने।

पुल का यह नजारा खुद ब खुद बताता है कि वो कितने सालों में तैयार होगा? चार साल पहले केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के हाथों नए सिरे से शिलान्यास के बाद भी जो पुल न बन सका उसे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जून 2018 में शुरू करा कर दिसम्बर 2018 तक बनवा देंगे। ये कुछ ऐसा ही हवाई ढकोसला है जैसे मोदी जी ने चुनाव से पहले 100 दिनों में काला धन लाने का वादा किया था।

सड़कों और पुलों के उद्घाटन एवं शिलान्यास के नाटक करने को मंत्री कृष्णपाल क्यों बेचैन हो रहे हैं? इस अफरा तफरी के पीछे एक ओर जहाँ 2019 का चुनाव है तो इसी बाबत सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते अमित शाह को खुश करना भी शामिल है। हरियाणा के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की 30 जून की कवायद में अपने नंबर बढ़ाने के लिए मंत्री जी ने सच ताक पर रख छोड़ा है।

मंझावली पुल की खामियां इतनी हैं जो कोई नौसिखिया भी बता दे। पुल से आने वाला सारा ट्रैफिक किस सड़क पर जाएगा इसकी कोई तैयारी नहीं। जो सड़क है वो दो पहिया चालकों के अलावा किसी को झेल नहीं सकती। ऐसे ही दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में वाहन कहाँ चलेंगे? क्या वहाँ की सरकार से मिल कर समुचित चौड़ाई की सड़क सुनिश्चित की गई, जबकि अभी वहाँ रेत के गुबार ही हैं?

मंत्री का दावा है कि इस पुल के बनने से फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच की दूरी सिर्फ 30 मिनट रह जाएगी7 जबकि सच्चाई ये है कि पुल बनते ही मंझावाली से फरीदाबाद तक 20 किमी के रिहाइशी स्ट्रेच पर कम से कम आधा दर्जन 30-30 मिनट के जाम ही लगा करेंगे। ऐसे में रोज दुर्घटना होना तय है और ग्रामीण इलाकों में दुर्घटना पर जनआक्रोश क्या रूप लेता है किसी से छुपा नहीं है।

इन बिन्दुओं का समाधान बिना ढूंढे ही मंत्री जी को पुल बनवाने की ऐसी जल्दी है कि उसमे सारा शहर मरता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो सिर्फ अपने पोस्टरों पर "जो कहा वो किया" का जुमला लगा ठेकेदार के पैसे से वोटरों को भंडारे खिला स्वार्थ साधने की फिक्र है। रही बात दिसंबर तक पुल पूरा करने की तो वह तो गुर्जर क्या, गडकरी और मोदी के बस का भी नहीं दिखता।

ग्रामीण विकास बना सीकरी सरपंच की मार्फ़त लूट का साधन, जांच करने वाले हैं खुद शामिल

बल्लबगढ (म.मो.) वर्ष 2010-15 में गांव सीकरी के सरपंच रहे चरण सिंह ने अपनी इस तैनाती के दौरान करोड़ों रुपये के विकास कार्य गांव में करने का फ़र्जीवाड़ा किया। इस बाबत गांव के ही एक युवक संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय रोशन लाल ने ज़िले के तमाम उच्चाधिरियों के अलावा विजिलेंस तथा मुख्यमंत्री विंडों तक पर शिकायतें कर लीं। सूचना के अधिकार कानून का भी इस्तेमाल कर लिया लेकिन किसी भी अधिकारी ने पूर्व सरपंच चरण सिंह को पूछा तक नहीं। कागज़ों में इन्क्वायरी की खानापूर्ति करके फ़ाइल को बंद कर दिया गया।

संजय ने **'मज़दूर मोर्चा'** को उपायुक्त फ़रीदाबाद को लिखी वह दरखास्त भी दिखाई जिसमें उन्होंने उन 21 विकास कार्यों का उल्लेख किया है जिनमें पूर्व सरपंच चरण सिंह ने घोटाला किया है। दिनांक 29 अगस्त 2017 को लिखी इस दरखास्त को एसडीएम बल्लबगढ के पास जांच हेतु भेज दिया गया। एसडीएम ने बीडीपीओ (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी) पूजा शर्मा से रिपोर्ट तलब की। पूजा शर्मा ने क्या रिपोर्ट देनी थी, उन्हें तो सारे घोटाले का पहले से ही ज्ञान था। सारा ज्ञान होने के बावजूद कोई कार्यवाही न करने को ही मिलीभगत अथवा घोटाले में हिस्सेदार कहा जाता है। लिहाज़ा रिपोर्ट को गोल-मोल ढंग से लिख कर ठिकाने लगा दिया गया।

पूर्व सरपंच द्वारा कराये गये विकास कार्यों में सर्वप्रथम हरिजन मुहल्ले में बनाई गई 27 लाख की वह सड़क है जिस पर बमुश्किल 7 लाख भी खर्च नहीं हुये। अगस्त 2011 में बनी इस सड़क के लिये न तो कोटेशनों का कोई ब्योरा है न ही बिलों और एमबी में इसका कोई ब्योरा दर्ज है।

दूसरे नम्बर पर भी इसी मुहल्ले की एक सीमेंटेड सड़क का ज़िक्र है जो वास्तव में बनी ही नहीं। काग़ज़ों में यह सड़क अगस्त 2014 में चौपाल के पास से समय सिंह के घर तक बनी दिखाई गयी है। इसका पूरा पैसा हड़प लिया। न तो कोई बिल है न कोई रिकार्ड। इसी तरह जून 2015 में 80 एमएम की 20, 000 टाइलों की खरीद दिखाई गयी। इनकी भी न तो कोई कुटेशन हैं और न ही एम बी में ब्योरा दर्ज है। इसके अलावा काम करने वाले मज़दूर व मिस्त्रियों का भी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इसी तरह पंडित विष्णु के घर से जगदीश नाई तक जो सीमेंट की सड़क बनाई दिखाई है वह वास्तव में कभी बनी ही नहीं।

सन् 2014 में पंडितों की चौपाल के लिये 20 लाख की ग्रांट सरकार से तथा कुछ पैसा पंचायत से लगा दिखाया है। लेकिन वास्तविक खर्च आधा भी नहीं हो पाया जो चौपाल की जर्जर हालत से बखूबी समझा जा सकता है। दिनांक 4 मार्च 2013 को बिल नम्बर 424 के तहत बालमिकी चौपाल में टाइलें लगाने हेतु सरकार से आई एक विशेष ग्रांट का भी सरपंच ने दुरुपयोग किया है। वर्ष 2013 में इसी तरह की एक और ग्रांट 15 लाख रुपये की गांव के स्टेडियम की चारदीवारी बनाने के लिये मिली थी, उसमें भी भारी घोटाला किया गया है। दिनांक 10.12.2014 के एक बिल नम्बर 148 के द्वारा राजपूत भवन के डीपीसी लेवल तक मिट्टी भराई का जो 15000 रुपये खर्च दिखाया गया है वह भी पूरी तरह फ़र्जी है। क्योंकि जिस जोहड़ से मिट्टी लाई गयी थी उसकी खुदाई का बिल सरपंच ने अलग से बना रखा है।

दिनांक 15.12.2012 को बनाया गया बिल नंबर 13 भी फ़र्जी है। इसमें पीडब्लूडी सड़क तक ड्रेन निर्माण दिखाया गया है जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिनांक 25.12.2013 को कोली चौपाल के नाम पर जो ढाई लाख का बिल नम्बर 125 बनाया गया था वह भी पूर्णतया फ़र्जी है। मौके पर एक पैसा भी नहीं लगा है। वाटर सप्लाई के पास बने सामुदायिक भवन में मिट्टी भराई का 15000 रुपये का बिल भी फ़र्जी है।

गांव के शमशान में दो शैड बनवाने पर जो 4 लाख का खर्च दिखाया गया है, उसमें भी फ़र्जीवाड़ा साफ़ दिखाई दे रहा है। मौजूदा खड़े शैड खुद बता रहे हैं अपनी लागत जो एक लाख से अधिक नहीं है। गांव के सरकारी स्कूल में 13600 रुपये की मिट्टी भराई का बिल भी फ़र्जी है क्योंकि वहां कभी कोई भराई हुआ ही नहीं। दिनांक 20.1.14 को चरण सिंह ने गांव के रतनवाल जोहड़ में जेसीबी से 7-8 फ़ीट गहरी मिट्टी खुदवाई का फ़र्जी बिल लगाया है क्योंकि यह मिट्टी पास वाली एक फ़ैक्ट्री को बेची गयी थी। इसमें पंचायत का कोई खर्चा नहीं लगा था। गांव की पीडब्लूडी रोड से बाल्मीकि चौपाल तक टाइलों की सड़क बनाने का बिल भी फ़र्जी है क्योंकि ऐसी कोई सड़क बनी ही नहीं। इसी तरह पंचायती इमारत में किरायेदार सिंडिकेट बैंक की रिपेयर आदि के बिल भी फ़र्जी हैं।

इनके अलावा और भी अनेकों फ़र्जीवाड़ों की लिस्ट काफ़ी लम्बी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अकेले किसी सरपंच की इतनी औकात नहीं होती कि वह सारा माल खुद ही हड़प जाय। इस लूट में सारा तंत्र शामिल होता है। जेई से लेकर एसडीओ, एक्सिन व एसई तक तो शामिल होते ही हैं दूसरी ओर बीडीपीओ व एसडीएम से लेकर उपायुक्त तक सभी की मिलीभगत एवं सहमति के साथ-साथ स्थानीय विधायक का संरक्षण जब तक न हो सरपंच अकेला एक पैसा भी नहीं डकार सकता। यही कारण है कि सरपंच की जो लूट गांव के संजय को दिख रही है वह न तो किसी अधिकारी को दिख रही है और न ही किसी राजनेता को।

बीडीपीओ पूजा शर्मा खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं

दिनांक 26.4.18 को पूजा शर्मा द्वारा, इस मामले में की गयी जांच रिपोर्ट को पढ़ने से यकीन हो जाता है कि पूर्व सरपंच चरण सिंह की लूट में उनका भी हिस्सा जरूर रहा है। वरना वे चरण सिंह को बचाने के लिये उन कामों को पूरा हुआ न दिखाती जो हुए ही नहीं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि चरण सिंह एमबी (पैमायश बुक) सहित सभी दस्तावेजों को गुम होने की बात कह रहा है और पूजा शर्मा उसको सत्य मान रही हैं। सरकार के करोड़ों रुपये खर्च होने से सम्बन्धित सारा रिकार्ड व तमाम दस्तावेज गुम हो जायें तो उसके विरुद्ध एफ़आईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गयी? पुलिस अपने आप ढूंढ निकालती उन तमाम दस्तावेज़ों को। इससे भी अधिक कमाल की बात तो यह है कि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त बीडीपीओ की जांच रिपोर्ट को उच्चाधिकारियों ने भी सही मान कर मामला समाप्त कर दिया। इससे उच्चाधिकारियों की कार्यशैली भी संदेह के दायरे में आती है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06